समुद्री चुनौतियां और अवसर

लेखक -सी. राजा मोहन (निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

16 जुलाई, 2019

"फारस की खाड़ी में मंथन भारत को चाबहार बंदरगाह में निवेश से परे अपनी रणनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।"

होर्मुज और मलक्का जलडमरूमध्य में हाल के घटनाक्रम से समुद्री मोर्चे पर भारत की उभरती चुनौतियों और अवसरों को प्रकट करने में मदद् मिलती है। देश के पश्चिम में, एक ओर ईरान और उसके पड़ोसियों के बीच क्षेत्र में बढ़ते तनाव और दूसरी ओर तेहरान और वाशिंगटन के बीच अंतर्राष्ट्रीय नौवहन पर हाई अलर्ट जारी है। कुछ अनुमानों के अनुसार, खाड़ी क्षेत्र में तेल टैंकरों पर हाल के हमलों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कम से कम 17 देश प्रभावित हुए हैं।

पूर्व में, चीन ने भी मलक्का जलडमरूमध्य से गुजरते अपने वाणिज्यिक नौवहन को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके अलावा, ईरान के आस पास केंद्रित खाड़ी क्षेत्र में तनाव साफ तौर देखा जा सकता है। हालांकि, मलक्का जलडमरूमध्य के तीन देशों – मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर – का कहना है कि उन्हें वास्तविक या संभावित खतरे का कोई सबूत नहीं दिख रहा है।

जहाँ एक तरफ कुछ लोगों का मानना है कि चीनी निर्णय अपने शिपिंग पर स्थानीय आतंकवादी हमले के बारे में खुफिया जानकारी पर आधारित हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ कईयों को संदेह है कि यह चीन द्वारा मलक्का जलडमरूमध्य में एक महत्वपूर्ण नौसेना की उपस्थिति स्थापित करने के संदर्भ में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है जिसे बीजिंग की आर्थिक 'जीवन रेखा' के रूप में देखा जाता है।

हर साल, लगभग 500 बिलियन डॉलर का व्यापार होर्मुज के जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। मलक्का जलडमरूमध्य से बहने वाले वाणिज्य का मूल्य 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक आंका गया है। हालांकि, होर्मुज और मलक्का जलडमरूमध्य में नौवहन के लिए खतरे जैसी बात नई नहीं है। तो फिर अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस बार इसमें नया क्या है। इस बार जो नया है वह है एशिया के संदर्भ में अमेरिकी बयान, जिसमें वह एशिया को खाड़ी में अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदारी लेने की बात करता है। पिछले महीने एक ट्वीट में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि एशियाई देशों को 'अपने जहाजों की रक्षा अब खुद करनी चाहिए।'

अमेरिका लंबे समय से भारतीय और प्रशांत महासागरों में समुद्री सुरक्षा की गारंटी देता रहा है। ट्रम्प अब इस ऐतिहासिक अमेरिकी भूमिका की लागत और लाभों पर सवाल उठा रहे हैं। यह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के रखरखाव के लिए लागत में अधिक से अधिक योगदान देने के लिए अपने यूरोपीय सहयोगियों पर अमेरिकी दबाव के समान है।

अमेरिका अब मध्य पूर्व से तेल आयात पर निर्भर नहीं है और एक प्रमुख हाइड्रोकार्बन निर्यातक बन गया है, जो ट्रम्प की पारंपरिक अमेरिकी प्रतिबद्धताओं की खाड़ी के लिए पूछताछ के लिए नया आर्थिक संदर्भ बनाता है। अपनी ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने ओसाका में अपनी बैठक में कथित तौर पर ट्रम्प को बताया था कि उन्होंने भारतीय नौसेना को खाड़ी में भारतीय तेल टैंकरों की रक्षा करने का आदेश दिया था।

ओसाका वार्ता के बाद से कहानी आगे बढ़ी है। जनरल जोसेफ डनफोर्ड, संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ सहित वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने खाड़ी को सुरक्षित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की योजना का खुलासा किया है। जापान और दक्षिण कोरिया कथित तौर पर इस तरह के गठबंधन में भागीदारी पर विचार कर रहे हैं।

जहाँ एक तरफ टोक्यो और सियोल अपने तेल के आयात को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त लागतों को बढ़ाने के बारे में अस्पष्ट हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजिंग खाड़ी में सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकता है। एक दशक पहले, जब पाइरेसी ने अदन की खाड़ी और अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए समस्या खड़ी की थी, तो चीन ने नौसेना की तैनाती शुरू की

जो आगे चल कर इस क्षेत्र में एक स्थायी सैन्य उपस्थिति में बदल गई।

इसके बाद ही चीन ने जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा स्थापित किया। बीजिंग ने खाड़ी और अरब सागर के समुद्री क्षेत्र में अपनी सैन्य भागीदारी तेज कर दी है। अमेरिका की मांग है कि एशियाई देश ऊर्जा के प्रवाह को सुरक्षित करने के लिए और अधिक प्रयास करे, जो चीन को खाड़ी में अपने लिए एक बड़ी भूमिका निभाने का अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है।

लेकिन यह अवसर भारत के लिए भी समान रूप से आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली, बीजिंग की तुलना में खाड़ी के सबसे करीब है और वह समुद्री क्षेत्र में अपनी समुद्री प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए बेहतर स्थिति में भी है। हालांकि, खाड़ी क्षेत्र के देश अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं की संभावित गिरावट के खिलाफ एक बीमा के रूप में अपनी सुरक्षा साझेदारी में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, दिल्ली में जनता की बहस ईरान के चाबहार बंदरगाह में अपने नियोजित निवेश के लिए खाड़ी संकट के निहितार्थ और तटस्थ दिखने के तरीके खोजने पर केंद्रित है।

वर्तमान स्थिति यह है कि मोदी सरकार खाड़ी में भारत की रणनीतिक संभावनाओं के बारे में थोड़ा और अधिक साहसपूर्वक सोच रही है। मोटे तौर पर, जैसा कि एशिया लगातार बढ़ रहा है और अमेरिका इंडो-पैसिफिक में सार्वजनिक वस्तुओं को प्रदान करने में अपनी भूमिका पर पुनर्विचार कर रहा है, दिल्ली को अपनी वस्तुओं को समुद्री देशों के गठबंधन के माध्यम के साथ-साथ अपने दम पर समुद्री सुरक्षा को बेहतर करने का लक्ष्य रखना चाहिए। मोदी ने अक्सर सुझाव दिया है कि भारत को 'अग्रणी शक्ति' बनने की आकांक्षा करने के साथ-साथ भारत को पड़ोस में क्षेत्रीय सुरक्षा की अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

GS World टीम...

अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ता विवाद

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते में संवर्धित यूरेनियम के उत्पादन को लेकर तय की गई सीमा का उल्लंघन किया और यूरोप को जवाबी कार्रवाई करने के खिलाफ आगाह किया।
- इसके साथ ही माना जा रहा है कि ईरान पी5+1 और यूरोपीय संघ के साथ 2015 में हुए ऐतिहासिक समझौते को तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ गया है, जिस दौरान यूरेनियम भंडारण की सीमा तय की गई थी।
- गौरतलब हो कि ईरान ने मई में घोषित अपनी योजना के आधार पर 300 किलोग्राम की सीमा पार कर ली है।
- ईरान द्वारा निर्धारित सीमा (3.7%) को पार किए जाने और 4.5 प्रतिशत संवर्धन करने की घोषणा देश के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रवक्ता बेहरूज कमालवंदी ने की।
- कमालवंदी ने संकेत दिया है कि इस्लामी गणराज्य कुछ समय तक संवर्धन के इस स्तर को बरकरार रख सकता है, जो एक परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90 प्रतिशत के स्तर से काफी नीचे है।

पृष्ठभूमि

- अमेरिका ने पिछले साल परमाणु सौदे से खुद को अलग कर लिया था और ईरान के महत्त्वपूर्ण तेल निर्यात और वित्तीय लेन-देन तथा अन्य क्षेत्रों पर सख्त प्रतिबंध फिर से लगा दिए थे।
- ईरान, जिसने समझौते को बचाने के लिए इसके अन्य साझेदारों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश के तहत घोषणा की थी कि वह संवर्धित यूरेनियम एवं हैवी वाटर भंडार पर लगाई गई सीमा को अब नहीं मानेगा।
- साथ ही धमकी दी थी कि वह और परमाणु प्रतिबद्धताओं को भी नहीं मानेगा जब तक कि समझौते के शेष साझेदार- ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी और रूस इन प्रतिबंधों से उसे छुटकारा नहीं दिलाते, खासकर तेल की बिक्री पर लगे प्रतिबंध से।
- वर्ष 2015 में हुए इस सौदे के तहत ईरान ने कभी भी परमाणु बम नहीं रखने, उसके परमाणु कार्यक्रम पर लगाई गई कठोर सीमाओं को मानने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाए जाने के बदले में आईएईए को निरीक्षण करने देने की प्रतिबद्धता जताई थी।

होर्मुज जलडमरूमध्य

- इसे ओरमुज जलडमरूमध्य के नाम से भी जाना जाता है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- यह ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है और यह 55 से 95 किमी. तक चौड़ा है।
- इसमें प्रमुख रूप से कीश्म, होर्मुज और हेंजम (हेंग्म) द्वीप स्थित हैं।
- सऊदी अरब, ईरान, यू.ए.ई., कुवैत और इराक से निर्यात किये जाने वाले अधिकांश कच्चे तेल को इसी जलमार्ग के माध्यम से भेजा जाता है।

संयुक्त व्यापक क्रियान्वयन योजना (JCPOA)

- ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिये वर्ष 2015 में ईरान तथा P5+1 देशों (अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्राँस, रूस और जर्मनी) के मध्य एक समझौता किया गया। इसे वियना समझौता के नाम से जाना जाता है।
- इसके अनुसार ईरान अपने परमाणु संयंत्रों की नियमित जाँच के लिये राजी हुआ, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वहाँ परमाणु हथियार बनाने पर काम नहीं चल रहा है।
- इस समझौते में ईरान द्वारा परिष्कृत यूरेनियम भंडार को 96 प्रतिशत तक घटाना और अपने सभी संयंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के लिये खोलना शामिल है।
- इस समझौते के तहत ईरान ने अपने करीब नौ टन अल्प संवर्द्धित यूरेनियम भंडार को कम करके 300 किलोग्राम तक करने की शर्त स्वीकार की थी।
- इस समझौते का मकसद परमाणु कार्यक्रमों को रोकना था। इन शर्तों के बदले में पश्चिमी देश ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटाने पर सहमत हुए थे।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. होर्मुज जलसंधि, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है।
2. मलक्का जलसंधि हिन्द महासागर व प्रशांत महासागर को जोड़ती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements-

1. Hormuz strait connects the Gulf of Persia and Gulf of Oman.
2. The Malakka strait joins Indian ocean and Pacific ocean.

Which of the above statement are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

Expected Questions (Mains Exams)

प्रश्न: होर्मुज और मलक्का जलडमरूमध्य के हाल के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए समुद्री मोर्चे पर भारत के समक्ष विद्यमान चुनौतियों एवं अवसरों को रेखांकित कीजिए। (250 शब्द)

Q. Considering the recent events of Hormuz and Malakka straits, underline the challenges and opportunities infront of India on oceanic front. (250 Words)

नोट : 15 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।